



चूरु

Rashtradoot

फोन:- 256906, 256907, फैक्स:- 01562-256908

वर्ष: 16 संख्या: 276

प्रभात

चूरु, रविवार 2 फरवरी, 2025

पो. रजि. न. चूरु/084/2019-21

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

'बजट में दिल्ली और बिहार के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई है'

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम् ने कहा, केन्द्रीय बजट का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना है

-रेपु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूगो-

नई दिल्ली, 1 फरवरी। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केन्द्रीय बजट असल में दिल्ली के मतदाता को लुभाने की कोशिश है।

अगर आप 7 लाख रुपए से 12 लाख रु. सालाना कमा रहे हैं तो आप टैक्स रूपए के लाये में जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्यम वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लोग हैं जो हर माह 60 हजार से एक लाख रु. तक कमाते हैं।

नई टैक्स व्यवस्था अखिल भारतीय स्तर पर सिर्फ 3.2 करोड़ लोगों को ही लाभ हो रहा है और दिल्ली में तो यह संभाला और पी कम है।

- चिदम्बरम् ने आरोप लगाया, बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, समाज कल्याण, कृषि क्षेत्र के बजट आठांटन में कटौती की गई है।
- चिदम्बरम् ने अनुसूचित जाति, जनजाति, ओडीसी तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के बजट में कटौती को कूर कदम बताया।
- उहोंने कहा, नई टैक्स प्रणाली में मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, खासकर, उहोंने जो हर माह 60,000 से एक लाख रुपए तक कमाते हैं, लैकिन पैट्रोल, डीजल में जीएसटी में कोई कटौती नहीं की गई है।
- उहोंने कहा, बेरोजगारी दूर करना सबसे अहम मांग है, पर, रोजगार सूजन की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

मदद मिल सके। बेरोजगारी दूर करने पर भजट में बिहार का भी ध्यान रखा गया है जो कि गया है जहां अगले वर्ष आम चुनाव होने वाले हैं।

बजट का मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना ही ना कि देश की जनता के जीवन की उग्रता को सुधारना।

चिदम्बरम् ने कहा अपना आठांटा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री नया विजन देने में पूरी तरह से असफल रही है, वे अवश्यक सुधार भी नहीं कर पाए। पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, पूर्वोत्तर के विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट में कटौती की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य वर्गों के लिए विधानसभा विजन के लिए विधायिक आठांटन के बजट से भी कटौती की गई है जो कूर कदम है।

बजट को रोटिंग देने के बारे में पूछा गया तो एक पवर वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली व बिहार के मतदाता इसे हार्द रोटिंग देंगे पर शेष भारत के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती।

नाबालिंग से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास

जयपुर, 1 फरवरी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर दिव्यने नाबालिंग कार्यालय छात्रों के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रोहित शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके हालत में 24 वर्षीय आभियुक्त रोहित शर्मा ने 2.55 लाख रुपए का जुमाना भी लागाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त

पॉक्सो कोर्ट ने 24 वर्षीय आरोपी युवक रोहित शर्मा पर 1.35 लाख रुपए का जुमाना भी लागाया।

ने नाबालिंग पीड़ितों को जन्मदिन की पार्टी में ले जाने का बहाना बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में कोई घटना नहीं खटकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेल बजट में रेल्वे को गत वर्ष जितनी राशि ही आवंटित की गई है।

- रेल्वे को गत वर्ष 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
- रेल्वे के आधुनिकीकरण की बड़ी-बड़ी घोषणाओं को देखते हुए इस वर्ष उम्मीद थी कि सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का 25 प्रतिशत रेल्वे को देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ।
- रेल्वे को 31,000 किलोमीटर रेल्वे ट्रैक का विद्युतीकरण करना है और रेल दुर्घटना नियोगित तंत्र "कवच" भी स्थापित करना है, साथ ही में इन इंजियों को भी प्रोत्साहन देना है। यह सब बजट प्रस्तावों में परिलक्षित नहीं हो रहा है।

कॉर्डोस के निर्माण की योजनाओं या आँकड़े के स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष एसीटी-हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए बढ़ाव देना है। यह अपराध की श्रेणी में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की ओर खुद दुखद मार्गदर्शक त्रैक्स खुक्कावार को पेश किये गये प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। "इकोनॉमिक सर्वे" में, सरकार ने भारतीय रेलवे, जिसे हाल ही के वर्षों में जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा

आँकड़े को मार्गदर्शक त्रैक्स धारा के लिए उठाए गये थे, उस समय के लिए उठाए गये थे।

वित्त वर्ष 2026 के लिये रेलवे को किया गया था रेलवे अवंटन 2.55 लाख करोड़ रुपए है, जिसना यह पिछले वर्ष था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2026 के लिये किया गया था वर्ष वर्ष की राशि की जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा को आवंटित करना चाहिए।

वित्त वर्ष 2026 के लिये रेलवे को किया गया था रेलवे अवंटन 2.55 लाख करोड़ रुपए है, जिसना यह पिछले वर्ष था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2026 के लिये किया गया था वर्ष वर्ष की राशि की जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा को आवंटित करना चाहिए।

वित्त वर्ष 2026 के लिये रेलवे को किया गया था रेलवे अवंटन 2.55 लाख करोड़ रुपए है, जिसना यह पिछले वर्ष था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2026 के लिये किया गया था वर्ष वर्ष की राशि की जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा

आँकड़े के सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए बढ़ाव देना है। यह अपराध की श्रेणी में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की ओर खुद दुखद मार्गदर्शक त्रैक्स खुक्कावार को पेश किये गये प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। "इकोनॉमिक सर्वे" में, सरकार ने भारतीय रेलवे, जिसे हाल ही के वर्षों में जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा

आँकड़े के सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए बढ़ाव देना है। यह अपराध की श्रेणी में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की ओर खुद दुखद मार्गदर्शक त्रैक्स खुक्कावार को पेश किये गये प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। "इकोनॉमिक सर्वे" में, सरकार ने भारतीय रेलवे, जिसे हाल ही के वर्षों में जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा

आँकड़े के सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए बढ़ाव देना है। यह अपराध की श्रेणी में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की ओर खुद दुखद मार्गदर्शक त्रैक्स खुक्कावार को पेश किये गये प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। "इकोनॉमिक सर्वे" में, सरकार ने भारतीय रेलवे, जिसे हाल ही के वर्षों में जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा

आँकड़े के सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए बढ़ाव देना है। यह अपराध की श्रेणी में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की ओर खुद दुखद मार्गदर्शक त्रैक्स खुक्कावार को पेश किये गये प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। "इकोनॉमिक सर्वे" में, सरकार ने भारतीय रेलवे, जिसे हाल ही के वर्षों में जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा

आँकड़े के सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए बढ़ाव देना है। यह अपराध की श्रेणी में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की ओर खुद दुखद मार्गदर्शक त्रैक्स खुक्कावार को पेश किये गये प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। "इकोनॉमिक सर्वे" में, सरकार ने भारतीय रेलवे, जिसे हाल ही के वर्षों में जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा

आँकड़े के सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए बढ़ाव देना है। यह अपराध की श्रेणी में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की ओर खुद दुखद मार्गदर्शक त्रैक्स खुक्कावार को पेश किये गये प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। "इकोनॉमिक सर्वे" में, सरकार ने भारतीय रेलवे, जिसे हाल ही के वर्षों में जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट धारा

आँकड़े के सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए बढ़ाव देना है। यह अपराध की श्रेणी में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की ओर खुद दुखद मार्गदर्शक त्रैक्स

